DIGICONTENT LIMITED
(formerly known as HT Digital Ventures Limited)
Registered Office: Hindustan Times House (2nd Floor)
18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi 110 001, India
+91 11 6656 1234 +91 11 6656 1270
www.digicontent.co.in corporatedept@digicontent.co.in
CIN: L74999DL2017PLC322147

04th August, 2022

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400 001

Scrip Code: 542685

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C-1, Block G,
Bandra- Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai- 400 051

Trading Symbol: DGCONTENT

Sub: Newspaper advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Re: 5th (Fifth) Annual General Meeting (AGM) of the Company via video conferencing/ other audio visual means

Dear Sir(s),

Please find enclosed herewith relevant page of **"Hindustan"** (Hindi - New Delhi Edition) and **"Mint"** (English - New Delhi Edition) newspapers, published on 4th August, 2022, intimating Shareholders regarding the 5th AGM of the Company scheduled to be held on Tuesday, 30th August, 2022 via video conferencing/ other audio visual means, along with other related information.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **DIGICONTENT LIMITED**

(Arjit Gupta)
Company Secretary

Encl.: *As above*

मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू, सभी तरह के कर्ज और महंगे होने की आशंका

महंगाई रोकने को रिजर्व बैंक फिर बढ़ा सकता है ब्याज दर

अनुमान

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की अगस्त मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक के बाद संभावना जताई जा रहा है कि कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। यदि आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोत्तरी की तो उपभोक्ताओं के लिए घर, कार और अन्य कर्ज और ज्यादा महगें हो जाएंगे। हालांकि, इसके बाद जमा पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोत्तरी होने की भी उम्मीद रहती है।

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की द्विमासिक बैठक पांच अगस्त तक चलेगी और इस बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा उसी दिन की जाएगी। जानकारों की राय में आरबीआई की तरफ से नीतिगत दरों में बढोतरी के बाद नई दरें कोरोना के पहले के स्तर पर पहुंच जाएंगी।

कोरोना महामारी से पहले यह दर 5.15 प्रतिशत पर थी। इस हिसाब से रिजर्व बैंक के पास अभी भी 0.25 फीसदी तक बढोतरी का पूरा मौका है।

0.90 फीसदी रेपो दर बढ़ा चुका है रिजर्व बैंक मई-जून में

0.25 से 50 फीसदी ब्याज और बढ़ने का अनुमान जता रहे विशेषज्ञ

4.90 फीसदी है मौजूदा समय में रेपो दर

महंगाई और आर्थिक वृद्धि बड़ी चुनौती

रिजर्व बैंक ने मई में 0.40 फीसदी और जून में 0.50 फीसदी का इजाफा रेपो दर में कर चुका है। बैठक में देश में बढ़ती महंगाई दर को लेकर चर्चा किए जाने की संभावना है। साथ ही विकास को गति देने पर भी विचार किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि दरें बढ़ने से महंगाई पर अंकुश तो लगता है लेकिन विकास दर घटने का भी खतरा रहता है।

एफडी पर ब्याज बढ़ने से निवेशकों को होगा लाभ

रिजर्व बैंक के रेपो रेट बढ़ाने के बाद एक तरफ जहां कर्ज महंगा हो रहा है वहीं एफडी पर मिलने वाले ब्याज में कमी से भी राहत मिलने लगी है। अब कई बैंकों की तरफ से अलग-अलग समय अवधि के लिए एफडी पर ब्याज बढ़नी शुरू हो गई हैं। मौजूदा दौर में सरकारी बैंकों के मुकाबले निजी क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों में सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है।

जमा पर फायदा देने में निजी बैंक आगे

एसबीआई दो करोड़ से कम के जमा पर सबसे ज्यादा पांच से 10 वर्ष की अवधि में वरिष्ठ नागरिकों को 6.3 फीसदी ब्याज दे रहा है और अन्य को 5.5 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है। डीसीबी बैंक 6.60 प्रतिशत, आरबीएल बैंक 6.55 प्रतिशत, इंडसइंड बैंक 6.50 प्रतिशत और कुछ छोटे बैंक आठ फीसदी तक ब्याज दे रहे हैं।

सेवा क्षेत्र की गतिविधियां चार माह के निचले स्तर पर

नई दिल्ली, एजेंसी। मुद्रास्फीति के दबाव के बीच बिक्री में नरमी के कारण जुलाई 2022 में देश में सेवा क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियां प्रभावित हुईं और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) गिरकर चार महीने के निचले स्तर 55.5 अंक पर आ गया। जून में पीएमआई 11 सालों के उच्चतम स्तर 59.2 अंक पर था।

एसएंडपी ग्लोबल की इस सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापारिक गतिविधियों में मुद्रास्फीति के दबाव के बीच बिक्री में कमी के कारण जुलाई में भारत के सेवा क्षेत्र की लय टूट गई। इसमें कहा गया है कि कंपनियों के मार्केटिंग पर जोर से उनको नए काम मिले लेकिन प्रतिस्पर्धा के दबाव और प्रतिकूल मौसम के कारण मांग ठंडी पड़ गई।

सर्वे में कहा गया, स्थिति में सुधार कम था लेकिन इसकी भरपाई कीमतों में सुधार से हो गई है। फरवरी से लागत खर्च धीमी दर से बढ़ रहा है जबकि जून की तुलना में उत्पादों का शुल्क कमजोर सीमा तक बढ़ा है। सर्वे में भाग लेने वालों के अनुसार, उच्च बिक्री की सूचना देने वाले सेवा प्रदाताओं ने अनुकूल मांग की स्थिति और उपयोगी विज्ञापन का उल्लेख किया। भारी प्रतिस्पर्धा और प्रतिकूल मौसम के कारण वृद्धि प्रभावित हुई है। एसएंडपी ग्लोबल ने कहा, सर्वे में प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि बिक्री में वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू बाजार पर आश्रित रही जबकि निर्यात बाजार में हालात और भी खराब हुए हैं।

नौकरियों के अवसरों का सृजन सुस्त रहा

पीएमआई सूचकांक के दौरान जुलाई में नई नौकरियों के अवसरों का सृजन नाम मात्र का रहा। एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की आर्थिक सह-निदेशक पोलियाम डी लिमा ने कहा कि इस सर्वे में बहुत सी चीजें उत्साहवर्धक दिखीं और कारोबार में वृद्धि मजबूत रही। इसी तरह मार्केटिंग के प्रयास और नई सेवाओं की पेशकश से नए कारोबार का विस्तार हुआ। डी लिमा ने कहा, इसके बावजूद भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में वृद्धि की रफ्तार जुलाई में टूट गई क्योंकि प्रतिस्पर्धा के दबाव, उच्च मुद्रास्फीति, खराब मौसम के कारण मांग घटी है।

बाजार 30s

शेयर बाजार

सेंसेक्स	निफ्टी
58350 +214	17388 +42.70

सर्राफा

	भाव	बदलाव
सोना	51974	-208
चांदी	57913	-1060

करेंसी डॉलर/रुपया **79.21 -0.68**

होंडा ने बाइक का विशेष संस्करण उतारा

नई दिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने नए डियो स्पोर्ट्स को लॉन्च करने की घोषणा की है जो सीमित अवधि के लिए ही उपलब्ध होगी। स्पोर्टी रैड रियर सस्पेंशन के साथ डिज़ाइन किये गए इस नए संस्करण को दो नए रंगों में पेश किया गया है। इसकी दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 68,317 रुपये से 73,317 रुपये के बीच है।

एयरटेल अगस्त में शुरू करेगी 5जी सेवाएं

नई दिल्ली। भारती एयरटेल ने बुधवार को कहा कि उसने उपकरण विनिर्माता कंपनियों एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ 5जी नेटवर्क समझौते किए हैं, जिसके तहत इस महीने उपकरणों की तैनाती शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि एयरटेल ने बीते दिनों 5जी स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी में बोली लगाई थी।

उबर ने जोमैटो में 7.8 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची

नई दिल्ली। ऑनलाइन कैब सेवा कंपनी उबर ने जोमैटो में अपनी 7.8 प्रतिशत हिस्सेदारी 3,088 करोड़ रुपये में बेची दी है। इन शेयरों की बिक्री 50.44 रुपये प्रति शेयर के औसत मूल्य पर की गई। वहीं फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने हिस्सेदारी खरीदी है।

DIGICONTENT LIMITED

CIN: L74999DL2017PLC322147
पंजीकृत कार्यालयः हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस (द्वितीय तल), 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001,
फोनः +91-11-6656 1234, **फैक्सः** +91-11-6656 1270,
ई-मेलः investor@digicontent.co.in, **वेबसाइटः** www.digicontent.co.in

डिजिकॉन्टेंट लिमिटेड की पांचवीं (5वीं) वार्षिक आम बैठक

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 5वीं ए.जी.एम. के आयोजन के नोटिस में निर्धारित कारोबार को सम्पादित करने के लिए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, सं. 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, सं. 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर 2021 और सं. 02/2022 दिनांक 5 मई 2022 **('एमसीए परिपत्रों')** और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 **('सेबी परिपत्रों')** के अनुसरण में, **डिजिकॉन्टेंट लिमिटेड** की **5वीं वार्षिक आम बैठक** (**'एजीएम'**), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों **('वीसी/ओएवीएम')** के जरिए, 5वें ए.जी.एम. आयोजित करने वाले सामान्य स्थान पर सदस्यों की उपस्थिति के बिना, **मंगलवार, 30 अगस्त, 2022 को पूर्वा. 11.00 बजे (भा.मा.स.)** आयोजित की जाएगी।

उपर्युक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों और कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसरण में, वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ ए.जी.एम. का नोटिस, केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा उन सदस्यों को भेजा जाएगा, जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स **('डीपी')** में पंजीकृत हैं।

ईमेल पता पंजीकृत करने/नवीकृत करने का तरीकाः

- जिन सदस्यों ने भौतिक रूप में शेयर रखे हुए हैं और कम्पनी में अपना ई-मेल पता पंजीकृत/नवीकृत नहीं किया है, https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक करके या केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड **('केफिन')**, यूनिटः **डिजिकॉन्टेंट लिमिटेड**, सेलेनियम बिल्डिंग टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-500032 को लिखकर अथवा einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल भेजकर उन्हें अस्थायी रूप से पंजीकृत/नवीकृत कर सकते हैं।
- जिन सदस्यों ने डिमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर रखे हुए हैं और अपना ई-मेल पता पंजीकृत/नवीकृत नहीं किया है, उस डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत/नवीकृत कर सकते हैं, जहाँ वे अपने डिमैट खाते रखते हैं।

वे सदस्य जिन्होंने डिमैट रूप में शेयरों को रखा हुआ है, अपना ई-मेल पता पंजीकृत करने हेतु उपर्युक्त लिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं या 5वीं ए.जी.एम. के नोटिस और वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के **सीमित प्रयोजन** हेतु einward.ris@kfintech.com में ईमेल अनुरोध भेजें।

कम्पनी अपने सदस्यों को 5वीं ए.जी.एम. के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (यानी रिमोट ई-वोटिंग और ए.जी.एम. के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा वोट देने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ए.जी.एम. में शामिल होने हेतु अनुदेश और ई-वोटिंग का प्रक्रिया (जिसमें वह तरीका शामिल है जिसमें वे सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं है, ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट दे सकते हैं), 5वीं ए.जी.एम. के नोटिस का भाग होगा। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ए.जी.एम. में शामिल हो तथा भाग ले सकते हैं।

5वीं ए.जी.एम. के आयोजन का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, कम्पनी की वेबसाइट www.digicontent.co.in; स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, की वेबसाइटों यानी बी.एस.ई. लिमिटेड www.bseindia.com में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com में और केफिन की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx में भी उपलब्ध होंगे।

कृते **डिजिकॉन्टेंट लिमिटेड**

हस्ता./-
अर्जित गुप्ता
(कम्पनी सचिव)

दिनांकः 3 अगस्त, 2022
स्थानः नई दिल्ली

शीर्ष शक्तिशाली महिलाओं में सीतारमण-नीता अंबानी

नई दिल्ली, एजेंसी। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिलायंस की निदेशक नीता अंबानी को फॉर्च्यून इंडियाज मोस्ट पॉवरफुल वुमैन इन बिजनेस-2022 की रैंकिंग में संयुक्त रूप से पहले पायदान पर जगह मिली है। चैनल की सीईओ लीना नायर तीसरे स्थान पर हैं।

रैंकिंग में फैशन ब्रांड नायका की सीईओ फाल्गुनी नायर, आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ, सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कली पुरी ने भी शामिल हैं।

इसमें शामिल होने वाली ईशा अंबानी सबसे युवा महिला हैं। फॉर्च्यून ने सीतारमण के लिए कहा कि अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से उपजी मुश्किलों का जमकर सामना किया।

- फॉर्च्यून की सूची में दोनों शीर्ष स्थान पर
- आर्थिक चुनौतियों से पार पाने में वित्त मंत्री सफल

सर्वे

देश के 42 फीसदी उपभोक्ता वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार

डिजिटल लेन-देन के साथ वित्तीय धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। पिछले तीन साल में 42 फीसदी लोग वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। साथ ही इसमें 74 फीसदी ऐसे हैं जो राशि वापस पाने में असफल रहे। लोकल सर्किल के अध्ययन में यह बात सामने आई है।

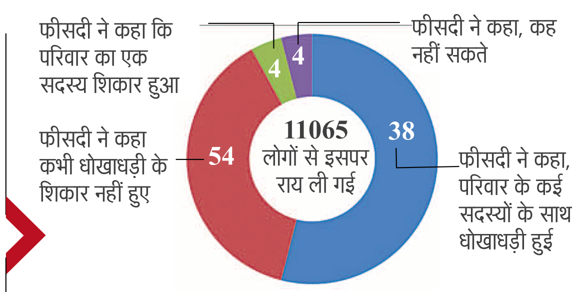

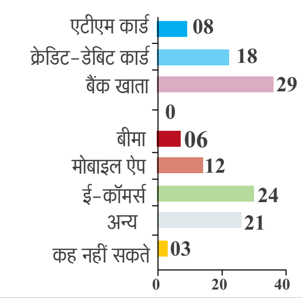

केवल 17 फीसदी उपभोक्ता राशि वापस पाने में सफल

- **10** फीसदी ने कहा कि संबंधित प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज कराया और राशि वापस मिली
- **07** फीसदी ने कहा कि संबंधित नियामक के पास शिकायत दर्ज कराया और राशि वापस मिली
- **36** फीसदी ने कहा कि मामला अभी भी लंबित है
- **19** फीसदी ने कहा कि कोई उपाय नहीं सूझ रहा
- **19** फीसदी ने कहा कि शिकायत नहीं दर्ज कराया

क्या है सर्वे में खास

इसमें कुल 32 हजार लोगों से राय ली गई है। इसमें 301 जिलों को शामिल किया गया। सर्वे में 43 फीसदी पहली श्रेणी के शहरों से, 27 फीसदी दूसरी श्रेणी के शहरों से और बाकी तीसरी, चौथी श्रेणी के शहरों के लोग शामिल हैं।

अपना देश

दबाव में नहीं आएंगे, बेरोजगारी के खिलाफ होगा प्रदर्शन : कांग्रेस

घेराबंदी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी के मुद्दे पर प्रदर्शन को रोकने के लिए पार्टी मुख्यालय की घेराबंदी की है। इसके साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पार्टी का कहना है कि वह दबाव में नहीं आएगी और शुक्रवार को इन मुद्दों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन करेगी।

नेशनल हेराल्ड मामले में यंग इंडियन का दफ्तर सील के बाद दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। पार्टी मुख्यालय की तरफ जाने वाली सड़क बंद कर दी गई। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए। इसके बाद पार्टी नेताओं ने मुख्यालय में रणनीतिक बैठक की।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, अजय माकन और अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि सरकार उनका प्रदर्शन रोकने के लिए यह घेराबंदी कर रही है। माकन ने कहा कि कांग्रेस ने शनिवार (पांच अगस्त) को महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी के मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान किया था। पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। माकन ने कहा कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराने के लिए मुख्यालय को पुलिस छावनी में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी दबाव में नहीं आएगी और इन मुद्दों पर देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा।

कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य मुख्यालय से प्रधानमंत्री के निवास की तरफ कूच करेंगे। वहीं, सांसद संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे।

नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील करने के दौरान मौजूद लोग। • एजेंसी

कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं : जयराम रमेश

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आरोप लगाया कि सरकार लोगों ध्यान भटकाने के लिए यह सब कर रही है। ताकि,महंगाई और बरोजगारी पर बात नहीं हो।

कांग्रेस मुख्यालय के पास से सुरक्षा घेरा हटाया

दिल्ली पुलिस ने बाद में कांग्रेस मुख्यालय के पास से सुरक्षा घेरा हटा लिया। राहुल गांधी के निवास 12 तुगलक लेन के आसपास सुरक्षा बंदोबस्त बरकरार रहा। कांग्रेस मुख्यालय में बैठक खत्म होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम राहुल गांधी के घर पहुंचे।

पीपीएससी सदस्य आधे रह जाएंगे

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा, उनकी सरकार ने खर्चों में कटौती के कदम के तहत पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) के सदस्यों की संख्या मौजूदा 10 से घटाकर पांच करने का फैसला किया है।

मान ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि इन 10 सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य खर्चों से राजकोष पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। उन्होंने कहा, सदस्यों की कमी आयोग की कार्य प्रणाली को किफायती बनाने के लिए की गई है। बचत के पैसों का इस्तेमाल लोक कल्याण में होगा।

संजीव भट्ट ने याचिका वापस ली

नई दिल्ली, एजेंसी। गुजरात कैडर के बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने हिरासत में मौत के तीन-दशक पुराने एक मामले में अपनी उम्रकैद की सजा निलंबित करने संबंधी याचिका उच्चतम न्यायालय से बुधवार को वापस ले ली।

संजीव भट्ट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी और कहा कि उच्च न्यायालय को कानून के अनुसार मामले से निपटने के लिए कहा जाना चाहिए।

पूर्वी कमान के प्रमुख असम दौरे पर

गुवाहाटी, एजेंसी। सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता चार दिवसीय दौरे पर असम के तेजपुर पहुंचे। इस दौरान वह चीन-भारत सीमा मुद्दों पर विचार-विमर्श में हिस्सा लेंगे। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया, कलिता चीन के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे अग्रिम इलाकों का दौरा करने के लिए मंगलवार को गजराज कोर के मुख्यालय, तेजपुर पहुंचे।

US plans to regulate crypto markets

It is looking to introduce a bill that would empower the Commodity Futures Trading Commission to regulate spot markets for digital commodities

Paul Kiernan
feedback@livemint.com
WASHINGTON

Leaders of a Senate committee are set to propose legislation that would assign oversight of the two largest cryptocurrencies, bitcoin and ether, to the federal agency that regulates milk futures and interest-rate swaps.

Senate Agriculture Committee Chairwoman Debbie Stabenow (D., Mich.) and top-ranking Republican John Boozman of Arkansas, are planning to introduce a bill Wednesday that would empower the Commodity Futures Trading Commission to regulate spot markets for digital commodities, a newly created asset class. Currently the CFTC has authority to police derivatives, such as futures and swaps, rather than underlying commodities.

The bill marks the latest salvo in an intensifying battle among federal agencies and congressional committees that oversee them over who will regulate crypto. Thirteen years after bitcoin was created, cryptocurrencies remain largely unregulated by the federal government, leaving investors without key protections from fraud and market manipulation. The competition for jurisdiction heated up in recent months as a meltdown in crypto markets underscored the need for guardrails in the eyes of many policy makers. The competition also reflects the industry's ramped-up lobbying presence in Washington and its push to reach more mainstream investors through Super Bowl ads and other high-profile marketing initiatives. "When there's a topic as hot as crypto, everybody wants a seat at the table," said Aaron Klein, a senior fellow at Brookings Institution who focuses on financial regulation. "The question is, are we going to have regulatory turf paralysis?"

In practical terms, for federal agencies such as the CFTC, Securities and Exchange Commission, and Federal Reserve, adding crypto to their remit would bring bigger budgets, greater influence and more job opportunities for officials who leave public service. For members of the congressional committees that oversee such regulators, a new industry in their sandbox would create another stream of lobbyists and campaign donations.

Washington has introduced a flurry of bills in recent months to draw jurisdictional lines. Sens. Cynthia Lummis (R., Wyo.) and Kirsten Gillibrand (D., N.Y.) unveiled a proposal in June that would create exemptions for cryptocurrencies in securities laws, banking statutes and tax code. In July, leaders of the House Financial Services Committee said they were working on a bill to grant the Federal Reserve a greater role in regulating some stablecoins, crypto tokens pegged against the dollar and other official currencies.

Agencies also are seeking to claim territory. CFTC Chairman Rostin Behnam, a former staffer to Ms. Stabenow, said last week his agency is "ready and well situated" to oversee spot markets for some cryptocurrencies. He has worked with his former boss for months to help craft legislation that would authorize the CFTC to do so, people familiar with the matter say.

Thirteen years after bitcoin was created, cryptocurrencies remain largely unregulated. AP

Meanwhile, SEC Chairman Gary Gensler has repeatedly demanded that cryptocurrency-trading platforms such as Coinbase Global Inc. register with the agency as securities exchanges akin to the New York Stock Exchange or Nasdaq. In May, the SEC nearly doubled the staff of an enforcement unit focused on cryptocurrencies.

"Four years ago when I started this job, there were some people that just thought this thing was all going to blow up and go away, that this was sort of a passing fad," said Kristin Smith, executive director of the Blockchain Association, a trade group representing crypto firms.

Now, she said, "We've got all these regulators suddenly vying for control."

After the SEC alleged in an insider-trading case in July that at least seven cryptocurrencies listed on Coinbase should have been registered as securities, Republican CFTC Commissioner Caroline Pham accused the SEC of "regulation by enforcement."

THE WALL STREET JOURNAL.

"The SEC is not working together with the CFTC," Ms. Pham said in an interview. "They go out unilaterally to try to establish precedent that's going to dramatically reshape the landscape as to what's a security and what's a commodity."

Ms. Pham has posted photos to her Twitter account of herself posing alongside crypto lobbyists and executives including Sam Bankman-Fried, the billionaire founder of trading platform FTX.

Ms. Pham said that crypto is one of the areas she is focused on, and, "I take pictures with everybody. Like, literally, everybody."

At the heart of the turf war are questions about how cryptocurrencies fit into the definition of a security, the legal classification that includes stocks and bonds.

A 1946 Supreme Court case created a test that focuses on whether investors buy an asset in hopes of profiting from the efforts of other people. If so, the issuer is required to register with the SEC and publicly disclose any information that may be material to the security's price.

Even though investors in bitcoin and ether rely on a network of users and programmers to validate transactions and perform software updates, cryptocurrency enthusiasts insist those groups are too decentralized for the assets to be regulated like securities. Instead, they argue, the assets should be considered commodities, which have a broader definition and no full-time regulator.

Firms such as Coinbase, FTX and Ripple have spent millions of dollars over the past year lobbying Congress to create a new category for digital commodities and empower the CFTC to regulate it. The agency has roughly one-sixth the head count of the SEC, and its rules are seen by the industry as easier to comply with than securities laws.

Washington has introduced a flurry of bills in recent months to draw jurisdictional lines

Crypto skeptics worry that creating a new legal concept for cryptocurrencies could create an alternative to securities registration for a wider variety of assets.

"People who are taking action that could undermine our securities law are playing with fire," said Dennis Kelleher, president of investor-advocacy group Better Markets. "You may love or hate the SEC, but transparent disclosure, clear rules...and enforcement is what builds trust and confidence in our markets."

The legislation being unveiled Wednesday would seek to exclude securities from the definition of digital commodities, making it narrower in scope than that of other crypto-related bills floated in recent months, such as the Lummis-Gillibrand proposal.

Because the bill is sponsored by the leaders of a committee, the Stabenow-Boozman bill also has better chances of advancing in the Senate than earlier proposals.

It would require any entity acting as a digital commodity platform—including crypto exchanges such as Coinbase and FTX—to register with the CFTC as trading facilities, dealers or brokers. The exchanges would have to monitor trading, protect investors from abuse and only offer assets that are resistant to market manipulation, among other requirements.

Platforms also would be obliged to disclose some information about the assets they list, such as operating structure and conflicts of interest. Such information would likely fall short of the extensive disclosures required by the SEC for securities.

The derivatives markets the CFTC currently oversees are dominated by professional investors, such as banks and hedge funds. Crypto markets, by contrast, draw legions of small investors who are more vulnerable to scams.

If the agency wins jurisdiction over bitcoin and ether, the CFTC would have to write rules from scratch to protect such investors.

"How robust would they be and how long would that take?" asked Tyler Gellasch, executive director of the Healthy Markets Association, an investor trade group.

©2022 DOW JONES & COMPANY, INC

DIGICONTENT LIMITED

CIN: L74999DL2017PLC322147
Registered Office: Hindustan Times House (2nd Floor)
18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110 001
Ph: +91-11-6656 1234; Fax: +91-11-6656 1270
E-mail: investor@digicontent.co.in
Website: www.digicontent.co.in

FIFTH (5TH) ANNUAL GENERAL MEETING OF DIGICONTENT LIMITED

Notice is hereby given that the **5th Annual General Meeting ('AGM') of Digicontent Limited** will be held on **Tuesday, 30th August, 2022 at 11:00 AM (IST)** through Video-Conferencing/ Other Audio-Visual Means **('VC/OAVM')** without the physical presence of the Members at a common venue, pursuant to General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, No. 17/2020 dated 13th April, 2020, No. 20/2020 dated 5th May, 2020, No. 02/2021 dated 13th January, 2021, No. 21/2021 dated 14th December, 2021 and No. 02/2022 dated 5th May, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs (**'MCA Circulars'**) and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (**'SEBI Circulars'**), to transact the business set out in Notice convening 5th AGM.

In compliance with the abovementioned MCA & SEBI Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 will be sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants.

Manner of registering/updating email address:

a. Members who hold shares in physical mode and have not registered/updated their e-mail address with the Company, can temporarily register/update the same by clicking on **https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx** or by writing to KFin Technologies Limited **('KFin')**, Unit: **Digicontent Limited**, Selenium Building Tower B, Plot No. 31 - 32, Financial District, Nanakramguda Serilingampally Mandal, Hyderabad- 500032 or by sending email to **einward.ris@kfintech.com**.

b. Members holding shares in dematerialised mode and have not registered/updated their e-mail address, can register/update their email address with the Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts.

Members holding shares in demat form can also use the aforesaid link to register their e-mail address or sending email request at **einward.ris@kfintech.com** for the **limited purpose** of receiving the Notice of 5th AGM and Annual Report for FY 2021-22.

The Company is providing the facility to the Members to exercise their right to vote by electronic means (i.e., remote e-voting and e-voting during the AGM) on the resolutions set out in the Notice of 5th AGM. The instructions for joining the AGM through VC/OAVM and the process of e-voting (including the manner in which Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address can cast their vote through e-voting), will form part of the Notice of 5th AGM. Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only.

Notice convening the 5th AGM and Annual Report for FY 2021-22 will also be available on the website of the Company at **www.digicontent.co.in**, websites of the stock exchanges where shares of the Company are listed viz. BSE Limited at **www.bseindia.com** and National Stock Exchange of India Limited at **www.nseindia.com** and website of KFin at **https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx** in due course.

For **Digicontent Limited**
Sd/-
Arjit Gupta
(Company Secretary)

Date: August 3, 2022
Place: New Delhi

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी-411018

जलनि:सारण विभाग

ई निविदा सुचना क्र. जलनि:सारण/मुख्यालय/5/7/2022-23

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिके कडून खालील नमुद केलेल्या कामासाठी ई टेडरिंग पद्धतीने परसेंट रेट निविदा मागविण्यात येत आहे.

1.निविदेचा दर भरताना एकूण निविदा रकमेतुन रॉयल्टी रक्कम व मटेरियल टेस्टींग रक्कम वगळून आलेल्या रकमेवर निविदा दर भरावा.
2. प्रचलित दराने GST बिलात अदा केली जाईल त्यामुळे GST वगळून दर द्यावेत.
3. रॉयल्टीबाबत मनपा जे धोरण ठरवेल ते आपणावर बंधनकारक राहील.

अ. क्र.	कामाचे नाव	एकूण निविदा रक्कम	रॉयल्टी रक्कम वगळून निविदा रक्कम	रॉयल्टीची रक्कम	मटेरियल टेस्टिंग चार्जेस	बयाणा रक्कम	अनामत रक्कम	कामाची मुदत (महिने)	निविदा फॉर्म फी GST सह (परत न मिळणारी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	काळेवाडी पंप हाऊस ते भाटनगर मलनि:स्सारण केंद्रापर्यंत नदीपात्र ओलांडून पाईप लाईन टाकणे	1,90,84,914	1,90,84,914	110	0	1,50,000	9,54,246	8	4,637
2	प्रभाग क्र. 11 चिखली स्वस्त घरकुल योजना परिसरात संप व पंप हाऊस बांधणे	1,60,22,570	1,60,22,570	19,859	0	1,50,000	8,01,129	12	4,637
3	मौजे कस्पटे वस्ती येथे मुळा नदीच्या कडेला पंपिंग स्टेशन बांधणे	1,42,49,442	1,42,49,442	24,338	0	1,42,495	7,12,472	12	4,637
4	चिंचवड केशव नगर सर्व्हे नंबर 292 येथील मैलापाणी पंपिंग स्टेशन लगतच्या मोकळ्या जागेत Energy Saving करीता नवीन आवश्यक त्या क्षमतेचे मैलाशुद्धीकरण केंद्र बांधणे	9,55,77,597	9,55,77,597	1,443	0	4,77,888	47,78,880	12	22,523
5	चिंचवड वाल्हेकरवाडी सर्व्हे नंबर 94 येथील जुन्या नादुरुस्त मैलापाणी पंपिंग स्टेशन च्या जागेवर Energy Saving करिता नवीन आवश्यक त्या क्षमतेचे मैलाशुद्धीकरण केंद्र बांधणे	10,00,28,924	10,00,28,924	12,394	0	5,00,145	50,01,446	12	37,430
6	कासारवाडी मैलाशुद्धीकरण केंद्रांतर्गत कै अकुंशराव लांडगे नाट्यगृह शेजारील जागेत 5 MLD क्षमतेचे STP बांधणे	10,90,34,145	10,90,34,145	11,892	0	5,45,171	54,51,708	12	37,430
7	पिंपरी चिंचवड शहराच्या सुशोभीकरणासाठी रस्त्यावरील C D works च्या Upstream बाजूस व Downstream बाजूस Chain Link Fencing करणे	35,57,515	35,57,515	0	0	35,575	1,77,875	12	2,397

निविदेचे वेळापत्रक

1	र.रु.50 लाखांचे अतिल निविदांसाठी ई निविदा उपलब्ध कालावधी	दिनांक – 03 /08/2022 ते 23/08/2022
2	र.रु.50 लाखांचे अतिल निविदा स्विकृती अंतिम दिनांक व वेळ	दिनाक – 23/08/2022 रोजी दुपारी 3.00 वाजेपर्यंत
3	र.रु.50 लाखांचे अतिल निविदा उघडणेचा दिनांक	दिनांक – 24/08/2022 दुपारी 3.00 नंतर शक्य झाल्यास
4	र.रु.50 लाखांचे वरील निविदांसाठी ई निविदा उपलब्ध कालावधी	दिनांक – 03/08/2022 ते 05/09/2022
5	र.रु.50 लाखांचे वरील निविदांसाठी ई निविदा उपलब्ध कालावधी	दिनांक – 05/09/2022 रोजी दुपारी 3.00 वाजेपर्यंत
6	र.रु.50 लाखांचे वरील निविदा उघडणेचा दिनांक	दिनांक – 06/09/2022 दुपारी 3.00 नंतर शक्य झाल्यास
7	निविदा पुर्व बैठक दिनांक व वेळ	दिनांक – 10/08/2022 दुपारी 3.00 वाजता
8	निविदा पुर्व बैठक ठिकाण	मा. सह शहर अभियंता, जलनि:सारण मुख्यालय,पिंपरी –18

जाहिरात क्र. 164
जा.क्र.जनि/2/कावि/516/2022
दिनांक : 02/08/2022

सही/–
सहशहर अभियंता
पिंपरी–चिंचवड महानगरपालिका,
पिंपरी–411018

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER
L-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

PUBLIC NOTICE

Government of National Capital Territory of Delhi has decided to grant licence in Form L-1 and Form L-IF for the wholesale vend of Indian Liquor and Foreign Liquor respectively in the National Capital Territory of Delhi for the licensing year 2022-23 w.e.f. 01.09.2022.

Th prescribed form for the grant of L-1 and L-IF licence can be obtained on payment of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand) only via online mode or by way of demand draft in favour of the Deputy Commissioner (Excise), Delhi, for each licence form during the office hours on any working day from the office of Commissioner of Excise, Government of National Capital Territory of Delhi, L-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002. Alternatively, the same can be downloaded from the website **http://excise.delhigovt.nic.in** under heading "News". However, in that case, a processing fee of Rs. 5000/- (Rupees five thousand) only for each licence form shall have to be deposited along with the application form by way of demand draft in favour of the Deputy Commissioner (Excise), Delhi. Applicants are required to apply online **also** at address **delhiexcise.gov.in**

Application received without complete information and supporting documents, as required in the prescribed form, along with its annexures, shall be liable to be rejected.

(KRISHNA MOHAN UPPU)
COMMISSIONER (EXCISE)

DIP/Shabdarth/0271/22-23

noida
NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
Administrative Building, Sector-6, Noida G.B. Nagar,(U.P)
Website : www.noidaauthorityonline.com

E-TENDER NOTICE

E-Tender are invited from firms/contractors registered with UPLC Lucknow for the following jobs against which bids can be uploaded and same shall be opened/downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of all tenders are available on Noida Authority's official website : **www.noidaauthorityonline.com** & **http://etender.up.nic.in** Please ensure to see these websites for any changes/ amendments & corrigendum etc.

(A) 1. 06/PGM/SM-WC-1/2022-23, Name of Work : Construction of Office Building for Noida Authority Sector-96, NOIDA (Balance Work). Cost : Rs. **8483.82 Lacs**

Which can be uploaded by date **10.08.2022** upto **5.00 P.M.** Pre-qualification shall be opened/downloaded on date **11.08.2022** at **11.00 AM**.

Principal General Manager
Noida.

CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

M.P. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T& D) COOPERATIVE FEDERATION
Sport Complex, 74 Bungalow, Indira Nikunj Nursery, Bhopal–462003
Phone No. : 0755-2674202 (MD), 2675258, 2674349, 2674263, Fax No. : 0755-2552628
E-mail : mpmfpit@gmail.com, Website : www.mfpfederation.org
No. : International Herbal Fair/9649 Date : 01.08.2022

NOTICE INVITING TENDERS FOR EVENT MANAGEMENT
INTERNATIONAL HERBAL FAIR AT BHOPAL (20th to 26th DECEMBER, 2022)

e-Tenders are invited for : Erection of furnished Domes , Stalls, Gates etc., for organizing International Herbal Fair, 2022 at Bhopal. Detailed instructions can be seen on **www.mptenders.gov.in**, **www.mfpfederation.org** as well. Tenders documents will be available online from 05.08.2022 at 11.00 Hrs.

IMPORTANT FACTS & SCHEDULE

(i)	Period of the Event	20th to 26th December, 2022
(ii)	Venue of the Event	Lal Parade Ground, Bhopal
(iii)	Pre-bid Conference	17.08.2022 from 15.00 Hrs.
(iv)	**Last date of Submission of Tenders**	**25.08.2022 by 15.00 Hrs.**
(v)	Opening of Technical Bids	26.08.2022 at 15.30 Hrs.
(vi)	Presentation by Eligible Tenderers	05.09.2022 at 12.00 Hrs.
(vii)	Intimation of results of Technical Bid	08.09.2022 at 15.00 Hrs.
(viii)	Opening of Financial Bids	12.09.2022 at 15.00 Hrs.

Tenders are to be submitted online on www.mptenders.gov.in
Amendments to NIT, if any would be published on website only, and not in newspaper.
For Stall Booking : Contact: 0755-2674349, Visit Website : www.mfpfederation.org
M.P. Madhyam/105747/2022 **MANAGING DIRECTOR**